[Shri Dabhi]

quantity rose from 24,000 lbs. to about 26,00,000 lbs. and you see how these tinctures are coming greatly in the way of the success of the prohibition in the State of Bombay. I welcome the Bill because it puts restrictions upon the import of these spirituous preparations in the State of Bombay.

I wish to make one more suggestion. Those who are trading in tinctures are coming the way of the success of prohibition. Clause 5 of the Bill reads as follows:

> "If any person contravenes any of the provisions of this Act or of any rules made thereunder, or the terms and conditions of any licence granted under such rules, he shall, for every such offence, be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both."

Alternative punishment—fine or sentence of imprisonment—has been provided as penalty in this clause. But if you want to make prohibition a success, deterrent punishment should be meted out to those who break the law. Not only those who drink these tinture come in the way of prohibition, but the real culprits are the traders, for if the traders are only fined Rs. 1,000, they will still go on with this trade, but if they are given a punishment by way of imprisonment as well as fine, then there would be some effect and I suggest to the hon. Minister that he should see that prohibition should succeed 100 per cent.

This measure is modelled on the lines of the Bombay Prohibition Act of 1948, under which the breaches of the provisions I have just now enumerated are made severely punishable both by fine and imprisonment. If the hon. Minister is serious about the success of this measure, I would request him to accept the amendments which I have suggested.

---

181 L.S.D.

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

THIRTY-FIRST REPORT

Shri Altekar (North Satara): I beg to move:

> "That this House agrees with the Thirty-first Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 27th July, 1955."

This is a simple report dealing with the allotment of time for the resolutions that have been tabled. and I commend it for the acceptance of the House.

Shrimati Renu Chakravartty (Bashirhat): May I ask one question. This report deals only with the allotment of time, and not the adoption of the ballot procedure.

Shri Altekar: That is contained in the Thirtieth report. This relates only to allotment of time for the resolutions.

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

> "That this House agrees with the Thirty-first Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 27th July, 1955."

The motion was adopted.

RESOLUTION *RE* CENTRAL AGRICULTURAL FINANCE CORPORATION

Mr. Deputy-Speaker: The House will now proceed with the further discussion of the following resolution moved by Shri S. N. Das on the 22nd April 1955:

> "This House is of opinion that immediate steps be taken to establish a Central Agricultural Finance Corporation with its branches all over the States to provide credit facilities for agricultural operations in the country."

[Mr. Deputy-Speaker]

There is also the amendment moved by Shri N. B. Chowdhury on the last occasion.

The House has already taken an hour and a half over this resolution. The time allotted is three hours. So an hour and a half is left. Normally, an hon. Member is given fifteen minutes. I find that hon. Members have given notice of certain amendments. They may move them.

Shri Sinhasan Singh (Gorakhpur Distt.—South): I beg to move:

> "That in the Resolution, after the words "credit facilities." *insert* "at nominal interest".

Shri B. K. Das (Contai): I beg to move:

That for the original Resolution, the following be substituted.

> "This House is of opinion that immediate steps be taken to establish a Central Agricultural Finance Corporation with its branches all over the States to provide credit facilities for agricultural development in the country including preservation and improvement of cattle, development of fisheries and production of protective foods."

Shri Bogawat (Ahmednagar South): I beg to move:

> That in the Resolution, *after* the words "agricultural operations". *insert* "as well as for the improvement of agricultural lands and for irrigating the lands."

Mr. Deputy-Speaker: Amendments moved:

> That in the Resolution, *after* the words "credit facilities" *insert* "at nominal interest".

That for the original Resolution, the following be substituted.

> "This House is of opinion that immediate steps be taken to establish a Central Agricultural Finance Corporation with its branches all over the States to provide credit facilities for agricultural development in the country including preservation and improvement of cattle, development of fisheries and production of protective foods."

> That in the Resolution, *after* the words "agricultural operations" *insert* "as well as for the improvement of agricultural lands and for irrigating the lands."

It is now 2-35 and if the House is prepared to sit five minutes more, we shall rise at 5-5.

Pandit D. N. Tiwary who was in possession of the House on the last occasion will continue his speech.

पंडित डी० एन० तिवारी (सारण दक्षिण): विगत २२ अप्रैल को जब यह प्रस्ताव सदन के सम्मुख प्रस्तुत हुआ, उसके बाद स्टेट बैंक आफ इंडिया बिल और रिजर्व बैंक एमेन्डमेंट बिल भी पास हुए, जिन से आशा थी कि जल्दी से जल्दी कृषकों की दशा सुधारने के लिए कोई कार्रवाई की जायेगी। हम लोग आज तीन महीने बाद या उससे भी अधिक दिनों पर यहां मिल रहे हैं। अभी तक मालूम नहीं हुआ कि इन तीन महीनों के बीच में गवर्नमेंट ने किसानों की दशा सुधारने के लिये स्टेट बैंक आफ इंडिया की मारफत या रिजर्व बैंक आफ इंडिया की मारफत कोई कदम उठाया या नहीं उठाया। मैं उस वक्त कह रहा था कि सरकार की कुछ ऐसी आदत होती है कि वह विलम्ब से काम करती है। जब काम का समय निकल जाता है तब उस काम को किया जाता है। आप देखेंगे कि तकावी का लोन बंटता है, खास कर जब कोई नेचुरल कलैमिटी आती है, जैसे बाढ़ वगैरह हैं, लेकिन वह बंटता कैसे है? जब बाढ़ समाप्त हो जाती है, लोगों के खेत बोये जा चुके होते हैं और जब कृषक अच्छे या बुरे बीज महाजनों से ले कर बो चुके होते हैं, तब उनको तकावी लोन मिलते हैं। नतीजा यह होता है कि उस पैसे को किसान लोग खेत में न लगा कर, क्योंकि फसल का समय तो बीत जाता है, उसे अपने खाने पीने

कर देते हैं। उसके बाद जब रुपये की वसूली का समय आता है तो न किसानों के खेत में फसल ही होती है और न वह रुपया ही दे सकते हैं। जब जब प्रासेस वारेन्ट इश्यू होते हैं तो जो लोग वसूली करने आते हैं उनको कुछ दे ले कर उस वारेंट को किसान टालता है। और इस तरह से दो, चार, दस मर्तबा टालने में प्रासेस का खर्चा बढ़ जाता है और उनको डेढ़ा या दूना रुपया देना पड़ता है, नजराने के अलावा। नजराना भी जोड़ लिया जाये तो जो तकावी उनको मिलता है उसका तिगुना कम से कम देना होता है।

मैं कह रहा था कि सरकार जो काम करती है वह समय के बाद होता है। मैंने इसकी तरफ भी माननीय मिनिस्टर का ध्यान आकर्षित करना चाहा था, लेकिन वह इस समय हैं नहीं।

The Minister of Revenue and Defence Expenditure (Shri A. C. Guha): There is another Minister there.

पंडित डी० एन० तिवारी: Perhaps he does not understand what I say मैं कह रहा था कि किसानों की हालत बड़ी खराब है। इसमें कोई शक नहीं कि सरकार किसानों के लिये कुछ करना चाहती है। माननीय मंत्री महोदय ने कहा था कि जब वह प्राइवेट मेम्बर थे तो उन्होंने बहुत बार इस ओर गवर्नमेंट का ध्यान आकर्षित किया था, वह कहते थे कि वह बड़े मुस्तैद पहले थे। मैं चाहता था कि उनकी वह मुस्तैदी बरकरार रहती, उनका जोश वही रहता। हम समझते थे कि शायद उनके गवर्नमेंट में चले जाने के बरस दो बरस बाद किसानों की दशा सुधर जाये, लेकिन वह हुआ नहीं। मैं इसी बात पर आ रहा हूं कि सरकार की कुछ देर करने की आदत हो जाती है और अच्छे काम करने का सारा उत्साह दूर हो जाता है। क्यों हो जाता है, इसे वह अच्छी तरह जानते हैं। मैं दूसरे प्रान्तों के बारे में तो जानता नहीं, लेकिन अपने बिहार प्रान्त में अधिकार के साथ बतला सकता हूं। मैं जानता हूं कि वहां कृषकों की क्या हालत है। उसके दो एक उदाहरण भी मैंने दिये कि समय पर रुपया न मिलने से वह लोग अपने रुपये को ठीक से खेती में इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं और इसी लिये वह समय से उस को दे भी नहीं पाते हैं। उन का कर्ज दिन प्रति दिन बढ़ता चला जाता है। मुझे महोदय ने यह भी कहा था कि किसानों को काफी मात्रा में कोआपरेटिव बैंक्स से या गवर्नमेंट से कर्जा मिलता नहीं है। अगर उनको तीन परसेंट कोआपरेटिव बैंक्स से, तीन परसेंट गवर्नमेंट से और चौदह परसेंट सम्बन्धियों से और बकिए महाजनों से मिलता है पर उनका काम नहीं चलता। उनको जब रुपये की जरूरत होती है तब उनको रुपया नहीं मिलता है। जब उनको रुपये की आवश्यकता होती है अगर उनको उस वक्त रुपया न दिया जाये तो इससे उन को कोई लाभ नहीं होता है। उनको रुपये की आवश्यकता खेती के काम के लिये होती है परन्तु वक्त पर कर्जा न मिलने से उनको बहुत नुकसान होता है। कोआपरेटिव बैंक जो हमारे यहां काम करते हैं उनकी दशा अत्यन्त शोचनीय है। अव्वल तो वह कोआपरेटिव बैंक जिस ग्राम में होता है वह उस ग्राम का प्रतिनिधित्व नहीं करता और दूसरे वह कुछ खास खास लोगों के हाथ ही में रहता है। इनमें से अधिकतर ऐसे लोग होते हैं जो कोआपरेटिव बैंक से रुपया लेकर गरीब किसानों को रुपया देते हैं। हमारे यहां आम तौर पर लोग महाजन के पास ज्यादा से ज्यादा जाना पसन्द करते हैं। इसके कुछ कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि जो रुपया उनको कोआपरेटिव बैंक से मिलता है उस से उनका काम चल नहीं सकता और दूसरे धीरे धीरे उस रुपये पर ब्याज पड़ कर वह इतना बढ़ जाता है जिसको फिर वे अदा नहीं कर सकते हैं। मनी-लेंडर्स बिल जो बिहार में पास हुआ है उसके मुताबिक दुगने से ज्यादा रुपया, असल को मिला कर, काश्तकारों को देना नहीं पड़ता है लेकिन यह उसूल कोआपरेटिव बैंक्स पर लागू नहीं होता है। कोआपरेटिव बैंक्स के केस में अगर जो रुपया लिया जाता है उस पर सूद बढ़ने के बाद उसकी यदि रकम दुगनी और तिगुनी भी हो जाये तो भी कर्जा देना पड़ता है। सरकारी बैंक छह परसेंट सूद पर रुपया देते हैं लेकिन कृषकों को वह रुपया ६ परसेंट और १२ परसेंट सूद पर मिलता है। आप ऐसी हालत में खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि

[पंडित डी० एन० तिवारी]

जो खेती करने वाले हैं और जिन को रुपये की जरूरत रहती है और वक्त पर उनको रुपया न मिले तो वे कहां जायें। उनको ऐसी हालत में महाजनों के पास जाना पड़ता है और उनसे बहुत ज्यादा दर पर रुपया लेना पड़ता है। ऐसा करने पर वे लोग मजबूर हो जाते हैं क्योंकि उनको कई बार तकावी का रुपया वापस करना होता है और कई बार जिन दूसरे लोगों से उन्होंने रुपया लिया है उनको वापस करना होता है। वे ऐसा अपने खेतों को मार्टगेज करवा कर रुपया लेते हैं। यह हालत किसानों की है। यह हालत उन किसानों की है जो बिहार में रहते हैं और मैं दूसरे प्रान्तों की बात नहीं जानता। वहां पर बड़े बड़े कारखाने भी नहीं हैं जहां जा कर उनके लड़के नौकरी कर सकें और कुछ कमा सकें। दूसरे प्रान्तों में जहां पर कारखाने हैं वहां किसानों के लड़के जा कर नौकरी करते हैं और पैसा कमा कर घर भेज देते हैं और उनका काम चल जाता है। बिहार में जो एक दो कारखाने हैं भी जैसे टाटा का और सिंदरी का कारखाना। इन कारखानों में जितने भी बड़े बड़े नौकरी वाले हैं वे दूसरे प्रान्तों के हैं और जो बिहार के लोग हैं वे इन में कुली इत्यादि का ही काम करते हैं। हमारे यहां काश्तकारों के लिये कोई और दूसरे साधन नहीं हैं जिनको अपना कर वे अपना काम चला सकें।

[Pandit Thakur Das Bhargava *in the chair*].

इसीलिये मैं आप से कहूंगा कि आप जो यह विचार कर रहे हैं कि हर सब डिविजन में स्टेट बैंक की शाखाएं खोली जायें यह आप कब करेंगे और मेरा ख्याल है कि जब तक आप इस में सक्सेसफुल होंगे उस वक्त तक किसानों की रीढ़ टूट जायेगी।

माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि सन् १९७१ तक और सन् १९८१ तक हमें अधिक अन्न की आवश्यकता होगी और हमें किसानों को हर प्रकार की मदद देनी चाहिये। मैं तो यह कहता हूं कि हिन्दुस्तान में अन्न की कभी कमी नहीं हो सकती बशर्ते कि किसानों को हर किस्म की फैसिलिटीज दी जायें जैसी कि आप बिजनेसमैन को देते हैं। बिजनेसमैन को आप क्रेडिट की फैसिलिटीज देते हैं और इसी किस्म की और कई फैसिलिटीज देते हैं अगर इसी किस्म की फैसिलिटीज आप उनको दें तो वे आप को और अधिक अन्न पैदा कर के देंगे तब आपको अन्न बाहर से नहीं मंगाना पड़ेगा। मैं तो यहां तक कहता हूं कि अब जब कि उनके पास सिंचाई का प्रबन्ध भी नहीं है वे अन्न की जरूरतों को पूरा कर सकेंगे।

आपकी जो स्कीम है उसमें आपने कहा है:

> "It will be very difficult to realise agricultural credit through a Central Organisation. I hope the hon. Member will realise that to have an apex without a basis is not an architecturally feasible proposal."

मैं सोचता हूं कि आपकी कोओप्रेटिव की आर्गनाइजेशन ऊपरी सतह से चलती है यानी प्राविंशल बैंक, डिस्ट्रिक्ट बैंक, सब-डिविजनल बैंक इत्यादि यह ठीक नहीं है। इसके बजाय अगर एक थाने को कोओप्रेटिव यूनिट रखा जाये और उसका सीधा सम्बन्ध सब डिविजनल स्टेट बैंक से हो तो यह बहुत अच्छा होगा। इससे खर्चा भी कम होगा और कम सूद की दर पर किसानों को कर्ज मिल जाया करेंगे। अब जो कुछ सूद रिजर्व बैंक ले लेता है, कुछ प्राविंशल बैंक ले लेता है, कुछ सब-डिविजनल बैंक ले लेता है, और इस तरह से जब रुपया किसानों को दिया जाता है तो उससे सूद की दर ज्यादा हो जाती है। इसलिये मैं सुझाव देता हूं कि थाने को एक यूनिट बना कर उसका सीधा सम्पर्क सब-डिविजनल बैंक से होना चाहिये और उसी की रिकोमेंडेशन पर कर्जा दे दिया जाये तो बहुत सी बाधायें दूर हो सकती हैं।

मैं एक दूसरा सजेशन भी देना चाहता हूं और प्रार्थना करता हूं कि अगर मेरा पहला सजेशन ... जाये तो इसको मान लिया जाये। आप स्टेट बैंक के मार्फत हर थाने में एक एक एजेंसी रखें और वहां पर आप अपना कोई अफसर रख सकते हैं। तब उस थाने के विलेज के लोगों को

कर्ज की जरूरत हो तो वहां की विलेज कोआपरेटिव और इस अफसर की रिकामेंडेशन पर आप सीधे रुपया दिलवा सकते हैं। ऐसा करने से बीच में जितने भी इंटरमीडियरीज होते हैं वे सब खत्म हो सकते हैं और किसानों को सीधे और कम सूद पर रुपया दिया जा सकता है। अगर आप इस बात को भी देखना चाहते हैं कि जिस काम के लिये कर्ज दिया जाता है उसी काम पर खर्च किया जाये तो वह भी आप कर सकते हैं। लेकिन सब से जरूरी चीज जो है वह यह है कि किसानों को ठीक समय पर और उपयुक्त मात्रा में रुपया मिले। आज कोआपरेटिव बैंक्स से रुपया लेने के लिये लोग इसलिये नहीं जाते हैं कि उनको मालूम है कि उनको दूसरे साधनों से भी रुपया मिल सकता है और कोआपरेटिव बैंक से उनको उपयुक्त मात्रा में रुपया नहीं मिल सकता है। इसलिये अगर आप उनको उपयुक्त मात्रा में रुपया नहीं देते हैं जितना कि उनको खेती के काम के लिये जरूरी है तो वह रुपया वेस्ट जाता है। आज कल ऐसा होता है कि अगर किसी किसान को खेती के काम के लिये १०० रुपये की जरूरत होती है, बीज, खाद इत्यादि खरीदने के लिये और अगर आप उसको सिर्फ ४० रुपये ही देते हैं तो वह अपना काम नहीं चला सकता है। परिणाम यह होगा कि वह रुपया वेस्ट हो जायेगा। जब तक इस बात का ठीक इन्तजाम और उपाय न होगा कि किसानों को फसल बोने के लिये पर्याप्त मात्रा में रुपया मिल जाये, तब तक उनकी अवस्था नहीं सुधर सकती है। आप वेयर-हाउस बनाने की बात सोच रहे हैं। तब आपको यह काम करना होगा कि हर फसल के बाद अन्न के रूप में रुपया लें और वेयर-हाउस में जमा कर दें। इससे गृहस्थों का बोझ कम होगा और आपका रुपया भी सुरक्षित रहेगा। ज्यादा समय नहीं है, इसलिये मैं कुछ अधिक नहीं कहना चाहता हूं। आप की नीयत पर किसी को शक नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी पुरानी - लाल फीते वाली पुरानी - और अनुपयुक्त समय पर और अनटाइमली काम करने का तरीका छोड़ दें, तो गृहस्थों की भलाई होगी और सरकार का रुपया भी महफूज रहेगा।

Shri Barman (North Bengal- Reserved—Sch. Castes): I fully support the resolution and the spirit of the resolution. It is a tragedy that though we are functioning in a democracy 70 per cent. of our population who are nowadays in dire necessity of money are not being properly looked after. All the resources that they had have dried up and yet their cries are still unrecorded. We have heard of the Industrial Finance Corporation. In the morning we had the Bill and in the afternoon we passed it. But, so far as this 70 per cent. of our population is concerned, we are crying for it since two decades and it is still under consideration.

I only want to stress two facts. With the passing of the Money-lenders' Bill in different States the one source of finance to agriculturists has dried up. Further, with the passing of State Acquisition Bills in different States the source of finance for the agriculturists through the middle men who used to apply the bulk of the finance has also dried up. In my State recently there had been a very unfortunate situation. On the one hand the middlemen, who under the law had to relinquish all the land that he had over the ceiling fixed did not supply any finance, bullock or anything to the tiller, and on the other the State also had no definite plan how to implement the provisions of the law and get the surplus land over the ceiling fixed from the middlemen. I know that the problem has not yet been solved.

I know that the State Bank has now undertaken the responsibility of rural finance. What I want to say is that taking up of responsibility is one thing and the actual discharging of it is another. The banking rules and regulations are so strict that besides the opening of banks—400 at present and more later on—I do not know how long the Government will take to frame the rules and procedure on the basis of which the branches of the State Bank will finance agriculture in the rural area.

[Shri Barman]

They will deal with multifarious forms of financial business and this will be one of the tasks. Therefore, I think that the present resolution brought before the House is worth considering. It may be considered as to whether this Agricultural Finance Corporation may be set up and this Corporation may be financed by the State Bank so that this Agricultural Finance Corporation being an independent body will be solely concerned with the task of devising ways and means of financing agriculture in rural areas. In that way, I think, there is the necessity for a Central Agricultural Finance Corporation. There will be branches, no doubt, under it in every State and in every district. But, this Central Corporation, if it is set up, will have the sole responsibility and duty to devise ways and means to help agriculture.

We are nowadays in a happy and comfortable position because we have got surplus in foodstuffs as our agricultural department says. We should at the same time realise that as things are changing fast, if there be no substitute to finance agriculture in place of the money-lenders and the middlemen who used to finance before, then agriculture will suffer in such a way that we may again have the calamity that we had experienced before. I submit that the Government should not deal with it in a light way. Whether they do it with the help of the State Bank or whether they think that an independent corporation shall be helpful for the purpose, we on our side, on behalf of the agriculturists, demand that Government should devise ways and means as quickly as possible so that before the next agricultural season comes everything may be ready to finance the agriculturists. That is my only submission.

Shri Bogawat: This is a resolution which is most useful and I must thank Shri S. N. Das for bringing it before the House, because there is a very big need for the agriculturists to have monetary help. You know, Sir, that there are several laws passed by the State Governments and among these laws the Money-lenders' Bill and the Tenancy Bill have brought so much difficulty that the money-lenders do not take any licence and give money to the agriculturists when they are in need. Similarly, in the Tenancy Bill there are some provisions by which they are not allowed to mortgage their land or sell their land even if they are in difficulty. Of course, these laws are passed for the protection of the agriculturists; that I can understand. But, the Government is aware of the amount of indebtedness of the agriculturists and when crores of rupees are needed for agricultural operations it is no use having any bank and providing only Rs. 20 or allow some amounts by way of *taccavi*. That is quite insufficient. For the last several years the agriculturists are suffering so much that another class has sprung up and without licence. These landlords are a class from the agriculturists themselves. They charge such heavy rate of interest that it ranges from 37:5 per cent. to 75 per cent. The needy and the poor agriculturists have to borrow money at very heavy rates of interest because they are in need of seed, bullocks and other agricultural implements. So, if we have really to help the needy agriculturists, then it is the bounden duty of every good Government to see that there are agricultural finance corporations on the model of, the Industrial Finance Corporation. It is a good thing that we are helping our industries, and lakhs of rupees are advanced to the industrialists but no attention is given to the very important problem of the agriculturists. It is a very long time since the Government has not done much, when the Government really ought to have cared for this big class which consists of 70 per cent. of the population. In my district there is always scarcity every third or fourth year and in some for the last three or four years, except one *kharif* crop, there is much scarcity, and the poor agriculturists have left and are

leaving the districts, especially Sholapur, Ahmednagar and part of Poona. This time also there is no good rain. The peasants are in a horrible condition. Even though there are some credit societies, they advance only Rs. 200 or Rs. 300 and take all the lands as charge. Further, the agriculturists are not able to get the *taccavi* loan. Even in the grant of *taccavi* there are too many difficulties. There are hundreds of thousands of applications and every few people get *taccavi* and even then there are other difficulties. It is an open secret that these *talatis* and circle inspectors are a nuisance. There are complaints—a thousand and one complaints—that they are charged 10 per cent. and 20 per cent. if *taccavi* is made available. These undesirable things are going on. So, in these circumstances, I request the Government to be very attentive and think about this very important problem if at all they want our agriculturists to prosper. The prosperity of the country depends on the prosperity of the agriculturists and if we do not give proper attention to this important problem, then it is not possible for years to come to see to the prosperity of that class for which the Government is very keen. So, may I request the Government not to sleep over this very important problem and see that agricultural finance corporations are at once established and the needy and poor agriculturists are helped immediately.

3 P.M.

I can give a number of instances. When an agriculturist wants to dig a well he is not able to get money. Formerly, the State Governments used to give money, but now, as the agriculturists are indebted owing to scarcity, they are not able to dig wells. There are so many people in the villages suffering under this difficulty. There are certain percolation tanks. For this also they want to have the tanks themselves. They want to take loans and these loans are also not available. There is a consciousness among the agriculturists to improve their conditions themselves but there is need for help. So, if we consider all these points, it is very essential to bring into force this resolution brought by my hon. friend.

I have put an amendment to this resolution. It is this:

> *After* the words "agricultural operations" *insert* "as well as for the improvement of agricultural lands and for irrigating the lands".

So, it is not only for agricultural operations but also for the improvement of the agricultural lands or for irrigating the lands of the agriculturists, there is need for financial help and it can be done through such agricultural finance corporations. Otherwise, it is very difficult. When crores of rupees are needed, how can a bank, or say, the State Bank of India, manage the thing, when they give only a few lakhs for each district? That amount would not suffice and would not meet the needs of the agriculturists. So, without making a very big speech, I want to request the Government that they should kindly accept the resolution and I also want to request my friend that he would be pleased to accept my amendment. I want to make a very earnest and humble request to the Government that they will see or at least give an assurance that such agricultural finance corporations will be established soon.

Shri B. K. Das: In my amendment I have made no change in the main proposition that an agricultural finance corporation should be established without delay. I have only tried to emphasise certain aspects of agricultural improvement. That is the only difference that I have made.

Shri A. C. Guha the other day intervened in the debate to say what steps the Government are going to take or have already taken in this behalf. He pointed out that with the establishment of the State Bank of India and with the amendment of the Reserve Bank of India Act, the arrangements for rural credit would be adequate, and that there would be no dearth of funds for the supply of rural credit to the entire population. But the structure of credit will have to be built on co-operatives. We know that the report of the Rural Credit Survey

[Shri B. K. Das]

Committee has also pointed out the present condition of co-operatives in the country. They have put it in a nutshell, saying that co-operation has failed but co-operation must succeed. (*An Hon. Member: How?*). That is the question. We should guard against undue haste about setting up co-operatives with a view to facilitate rural credit. We know it, as a matter of fact, and experience, that when there was some arrangement for credit in rural areas, there were large numbers of co-operatives established in hot haste, and 90 percent of them have failed. Because of organisational weakness and the structural weakness, the co-operatives have not developed, and if, under the present circumstances also, we do not wait or we do not take proper care for proper development, the result will be the same.

I think it will be more dangerous because if the faith of the people in co-operatives is shaken, it will be very difficult to revive that faith. I was pointing out that rural credit will be available only if co-operatives are established throughout the length and breadth of the country. But we should make a proper assessment of our strength to build co-operatives. What has been our experience during these three years with our community development blocks? If we read the report of the Programme Evaluation Organisation, we find that they have not been able to give us a good number of co-operatives, although it was said that each family must belong to some co-operative or other. Although the report says that they are expecting hopeful results, still after the working of three years, with special officers to look after particular areas, we find that they have not been able to give us a large number of co-operatives. In a way I think it is better that they have not taken hasty steps. My object in supporting this resolution and proposing a corporation is that in addition to what we are going to do with respect to our co-operatives, some organisation should be built up which can deal directly with this problem in our rural areas. The present arrangement is very very inadequate, and although the arrangement that we are expecting through these organisations promises better results, it will take a good length of time. During the absence of such widespread and well-established co-operative organisations, we want that some assistance should be given directly; the endeavour of the co-operatives should be supplemented by an organisation like this. We have experience of these industrial corporations which deal with big, small and medium-sized industries. Under the present circumstances, we shall have little of big farmers. So, the pattern of this corporation may be slightly different; we shall have to go into those details later on. But I have no doubt in my mind that such a corporation is of utmost need and the investment for that corporation must come not only from the State but from private persons also. We should also take note of the fact that in every State there are new tenancy laws being enacted and a revolutionary change is being brought about in our rural areas. The general trend is that when the ceiling is put, the *bona fide* cultivator will have land to cultivate to the extent of 30 acres or 25 acres, because the ceiling may not go much further. If that cultivator has to wait for the establishment of co-operative organisations in his area, he will be deprived of credit that is of utmost need to him. I can also visualise a condition in which a cultivator may live in a remote area where it will take several years for the development of co-operative organisations: what will be the agency to supply credit to him? The present arrangement of granting *taccavi* loans etc. does not reach him. Therefore, if a corporation is set up, and if it begins to function, then a person who concentrates on the intensive cultivation of his land will be able to have an easy living which is very necessary for him.

The idea is not that we should not concentrate our efforts on building co-operatives. In fact, if we want that

credit should reach every small farmer, even a man possessing very little land, we must build co-operatives. The idea is to supplement that effort with the establishment of a corporation, the pattern of which we have got in our industrial sector. I cannot understand why it is impossible or difficult to have an organisation to have credit from different sources. If at the present moment our industrial sector has been receiving that credit from different sources, it is also proper and necessary and feasible that credit for the rural sector, for that agricultural sector, also should be provided from different sources.

श्री सिंहासन सिंह: यह भवन श्री एस० एन० दास का आभारी रहेगा जिन्होंने अपने प्रस्ताव के जरिये भवन का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित किया है। इस प्रस्ताव के आने के पहले रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने एक कमेटी आफ डाइरेक्शन रूरल सर्वे के लिये बनाई थी. उसकी रिपोर्ट भी सन् १९५४ से गवर्नमेंट के पास होगी, गवर्नमेंट का क्या ध्यान उस तरफ गया, हमें आपको अभी तक पता नहीं है। उस तरफ भी गवर्नमेंट का ध्यान जाये, इस हेतु भी यह प्रस्ताव आपके सामने है और जो गवर्नमेंट ने उस पर अब तक विचार किया है, वह हम को मालूम भी होगा।

इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में मेरा संशोधन यह है कि चूंकि रेट आफ इंटरेस्ट नहीं बताया गया है, इसलिये हम चाहते हैं कि नामिनल इंटरेस्ट लिख दिया जाये।

अब उस कमेटी के क्या क्या सुझाव हैं वह मैं आपको संक्षेप में बतलाना चाहता हूं। उसने तीन बातों पर विशेष तौर पर सरकार और जनता का ध्यान आकर्षित किया है। हमारा देश क्या है? क्या कर्तव्य हमारी गवर्नमेंट का होना चाहिये, उन्होंने बड़े साफ शब्दों में देश को इस तरह से परिभाषित किया है कि भारत का स्वरूप क्या है। अंग्रेजी में इस प्रकार कहा है:

> "India is largely rural. Rural India consists very largely of cultivators. Agriculture is the largest industry in the country."

यानी भारत अधिकतर ग्रामीण भारत है और ग्रामीण भारत अधिकतर कृषि प्रधान है और भारत का प्रधान व्यवसाय कृषि है। जिस भारत का प्रधान व्यवसाय कृषि हो और जिसके अन्दर हमारी कुल आबादी का, गत सेन्सस के आधार पर जो संख्या बताई गई है, ६९.८ प्रति शत जनसंख्या कृषि पर आधारित है, उसके लिये हमारी सरकार की तरफ से क्या कदम उठाये गये, यह सब लोगों के लिये विचारणीय है। सरकार ने करोड़ों रुपये व्यय किये, खेती को बढ़ाने के लिये ग्रो मोर फूड और अन्य अनेक आयोजन हुये, लेकिन कुछ काम नहीं चला। खाना भी काफी पैदा हुआ और आज झुकाव सस्ते की तरफ है। फसल के अधिक पैदा होने से और गल्ले के सस्ते होने से हमारा मसला बदल गया है। शायद किसी स्टेट या कुछ स्टेट्स के किसी वर्ग के कष्ट कुछ दूर हो गये हों, लेकिन आज ग्रामीणों की अवस्था और प्रायः उन ग्रामीणों की अवस्था जो छोटे छोटे खेतिहर हैं जिनकी संख्या बहुत अधिक है, गल्ले के सस्ते हो जाने के कारण और खराब हो गई है। उनकी अवस्था जो लड़ाई के जमाने में थी, आज उस से कहीं बदतर हो गई है। उनके खाने पीने की सामग्रियां और दूसरी सामान्य पारिवारिक आवश्यकता की चीजें महंगी हो गई हैं जब कि उनका गल्ला सस्ता हो गया है और उनकी बिक्री बहुत कम है। बाजार में उनके गल्ले की कोई बिक्री नहीं है। अभी थोड़े दिन हुये गुड़ और चीनी का मसला चला था। गुड़ का भाव गिरता गया। खेतिहर की खास पैदावार गुड़ है, गन्ने को कैश क्राप कहा जाता है। और वही खेतिहर की आमदनी का खास जरिया है। लेकिन होता यह है कि उनके पास पैसे की कमी होने के कारण उनके गुड़ को महाजन मनमानी कीमत पर ले लेता है और वह बेचने के लिये मजबूर हो जाते हैं। अक्सर यह देखा जाता है कि गुड़ की फसल में मालगाड़ियों की कमी पड़ जाती है। जहां जहां गुड़ की मंडियां होती हैं वहां गुड़ का भाव इतना गिर जाता है फिर भी काश्तकार उसको बेचने के लिये मजबूर हो जाता है क्योंकि उसके पास गुड़ को दूसरी जगह ले जाने का कोई जरिया नहीं होता है। जब गुड़ का समय खत्म हो जाता है तब गुड़ महंगा हो जाता है। लेकिन किसान ने तो उसको उसी समय बेच दिया जब कि गुड़ की पैदावार का समय था।

[श्री सिंहासन सिंह]

इस विषय पर पिछली मर्तबा डा० दंशमुख साहब से और प्रधान मंत्री से बात चीत हुई कि इसका कोई उपाय किया जाये ताकि गुड़ पैदा करने वालों को इतना नुकसान न हो। चीनी तैयार करने वाली जो मिलें हैं उन से किसानों को बल्क कुछ कीमत मिल जाती है, लेकिन आज भी बहुत सी मिलें हैं जो कि रुपया नहीं देती हैं। नतीजा यह होता है कि गुड़ वालों की हालत और बदतर हो जाती है। हां, एक कोआपरेटिव सोसायटी जरूर बन गई हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं हैं। इसलिये आज गल्ले के सस्ते हो जाने के कारण किसानों की हालत और भी खराब हो गई हैं।

एक बार हमारे प्रधान मंत्री ने बड़ी सुन्दर भाषा में कहा था कि हम ने जमींदारी तो मिटा दी लेकिन साथ ही गरीब किसानों को कर्जा देने की कोई व्यवस्था नहीं रक्खी। जमींदारी प्रथा के टूटने के पहले दो तरह के मार्ग थे काश्तकारों को बीज, खाद इत्यादि मुहैया करने के। काश्तकारों की हालत तीन वक्तों में बड़ी खराब हो जाती हैं। एक तो मार्च के महीने में जब कि लड़की लड़के की शादी का समय होता हैं। दूसरा भादों का महीना जब कि वह पैदा किया हुआ अपना गल्ला खा जाता हैं और तीसरे अगहन का महीना। पहले तो जमींदार अपनी जिम्मेदारी समझता था और अपनी रियाया और काश्तकारों को खिलाता था, उनको कर्जा देता था, उनकी लड़कियों को शादी के लिये पैसा देता था और जो सूद का रुपया होता था उसको वह धीरे धीरे लिया करता था, कभी कभी माफ भी कर दिया करता था। इसके अलावा छोटे बड़े मनी लेंडर्स अर्थात् महाजन हुआ करते थे, वह कर्जा देते थे, लेकिन जहां खलिहान में गल्ला आया, वह खलिहान में ही आ कर गल्ला उठा ले जाते थे और किसानों की अवस्था और भी बिगड़ती थी। लेकिन जब से हम ने दो कानून पास किये, एक तो जमींदारी एबालिशन का और दूसरा कर्जा मोचन। कर्जा भी तोड़ा और जमींदारी भी तोड़ी तो जो कर्जा देने वाले थे वह सोचने लगे कि आखिर कर्जा किस उम्मीद पर दें। गवर्नमेंट ने कानून बनाया, जो पहला कर्जा था वह साफ हुआ, आगे के लिये कोई वसूल करने का जरिया नहीं। अब जब जमींदार भी कर्जा नहीं देते, क्योंकि जमींदारी खत्म हो गई, तो छोटे काश्तकार जो हैं वह निराश्रित हो गये हैं। वह आज नहीं समझते कि उनके लिये स्वराज्य का रूप बदला हैं या नहीं। गांव गांव में हम नहरें बना रहे हैं, ट्यूब वेल खोल रहे हैं, इससे फायदा तो बहुत अच्छा हैं। लेकिन ट्यूब वेल से पानी पाने के लिये उनके पास आज पैसा नहीं हैं। उनका अधिकतर काम उधार चलता था, लेकिन इसके लिये कोई व्यवस्था नहीं की गई हैं। जो कोआपरेटिव सोसायटी थीं, बड़ी बड़ी क्रेडिट कोआपरेटिव सोसायटीज वह कर्जा देने की सहूलियत बढ़ाने के बजाय उन लोगों के लिये दिक्कत का कारण हुई। इस कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा हैं कि हमारी कोआपरेटिव सोसायटियां जो गवर्नमेंट की आश्रित थीं, बजाय काश्तकारों को मदद देने के उन पर हुकूमत ज्यादा करती थीं। रुपया तो कम ही देती थीं, हुकूमत ज्यादा किया करती थीं। हम आज हुकूमत के वातावरण में चल रहे हैं। जहां कहीं आप देखिये, आप को हुकूमत ही ज्यादा मिलेगी। कुछ रुपयों की सहायता देने का प्रश्न हो तो हुकूमत करने वाले पहुंच जाते हैं और उसी सहायता में बटवारा हो जाता हैं। तो कोई उपाय तो इस तरह का हो जिससे हुकूमत की कुछ डिलाई हो। ऐसा होने पर ही कुछ काम हो सकता हैं। इसलिये इस कमेटी ने बड़े सुन्दर शब्दों में सुझाव दिया हैं, और उम्मीद हैं कि हमारे अर्थ मंत्री ने उसको पढ़ा होगा, और विचार भी किया होगा। बड़ा सुन्दर सुझाव हैं। हम ने ७० की सदी जनता के लिये अब तक क्या किया, उनके लिये क्या सुविधाएं प्रदान कीं। हमारी किताबों में इसकी कोई गणना नहीं हैं। लेकिन १० की सदी से कम जो बड़े बड़े व्यवसायी हमारे हैं उनके लिये हम ने अनेक कारपोरेशन्स कायम कर दिये। इसी रिपोर्ट के अन्दर हैं कि हमारे यहां के १०.५ प्रति शत आदमी हैं जो कि इन्डस्ट्री में लगे हुए हैं। इन १०.५ परसेंट आदमियों के लिये हम ने बड़े बड़े इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन्स बना दिये, जिनका किस्सा कल भी भवन के सामने

मौजूद था कि उन में किस तरह से व्यय हुआ, सभी ने ऐसा किया था किसी किसी ने ही किया, वह तो इतिहास का विषय हो चुका है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्या हुई? हमें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। जो ९० की सदी लोगों के लिये अपनी सरकार का करोड़ों रुपया आप ने बैंक खोल कर दे दिया, उनकी मर्जी पर दे दिया, लेकिन जहां तक ७० की सदी जनता का सवाल है, उनके लिये हमारे सामने प्रश्न उठाया जाता है कि बड़ी विकट समस्या है, कुछ होगा या नहीं होगा, पता नहीं, और होगा तो कैसे होगा? इस पर बड़ी गम्भीरता से सरकार को विचार करना है क्योंकि इस मिक्स्ड एकानमी से, इन बड़े बड़े पूंजीपतियों को रुपया दे कर बड़ी बड़ी इन्डस्ट्रीज कायम कर के ही हम अपने मुल्क को आगे नहीं चला सकते। जब तक कि खेतिहर सुखसम्पन्न नहीं होगा तब तक हमारी उन्नति नहीं हो सकती। अगर खेतिहर आज दरिद्र है, उसके पास क्रय शक्ति नहीं है, खाने के लिये अन्न नहीं है तो सब गल्ला बाजार में ज्यों का त्यों पड़ा रह जायेगा, और कहीं पर उसकी बिक्री नहीं होगी, और हमारा सारा व्यवसाय ठंडा हो जायेगा। जिस देश के ७० फी सदी आदमी मन में दुखित हों, और उनके लिये सहारा न हो और २० फी सदी आदमियों के लिये कुल व्यवसाय निश्चित हो, वह उसी अनुपात से अच्छी व्यवस्था वाला नहीं कहा जा सकता। आप इस तरफ ध्यान दें और इस कमेटी ने जो अपना विचार प्रकट किया है उसमें उस ने बताया है कि गरीबी का कितना अनुपात है। इस कमेटी ने बड़ी मेहनत की है, २ लाख २० हजार परिवारों में उसने भ्रमण किया है और ७५ जिलों के ६०० गांवों की हालत को देखा है। इसलिये इस कमेटी ने जो सर्वे किया है वह बड़ी मेहनत के साथ किया है और हम सब को उनका आदर करना चाहिये। अगर हम किताबों में ही इन विचारों को पड़े रहने देंगे तो कुछ होना नहीं है। अगर हम सक्रिय आदमी हैं तो हम को उनके सुझावों पर विचार करना चाहिये। उन्होंने २२ वें चैप्टर में यह सुझाव दिया है :

"We recommend that for the next five years, after which the position should be reviewed, the Reserve Bank and the Government of India should make to the funds with which they are respectively concerned annual allotments of not less than the amounts specified below:

'(a) Rs. 5 crores, by the Reserve Bank of India, to the National Agricultural Credit (Long-term Operations) Fund;

(b) Rs. 1 crore, by the Reserve Bank of India, to the National Agricultural Credit (Stabilization) Fund;

(c) Rs. 1 crore, by the Government of India to the National Agricultural Credit (Relief and Guarantee) Fund under the Ministry of Food and Agriculture; and

(d) Rs. 5 crores in all, by the Government of India, to:

(i) The National Co-operative Development Fund and (ii) The National Warehousing Development Fund, both to be instituted under the National Co-operative Development and Warehousing Board'."

यह उनकी रिकामेंडेशन है। साथ ही उनकी रिकोमेंडेशन यह भी है कि आगे चल कर गूंज बैंकस कायम किये जायें और मार्केटिंग फैसिलिटीज भी दी जायें। आज उनके लिये कोई ऐसी फैसिलिटीज नहीं हैं जहां पर जा कर वे लोग अपना गूंज (गल्ला) रख दें और वहां से उस गूंज के बदले में ५० प्रतिशत या २५ प्रतिशत मूल्य भी ले लें। अगर ऐसा हो जाये तो हमारा काम चल सकता है। आज जितनी भी फैसिलिटीज हैं वह बड़े बड़े मर्चन्ट्स के लिये ही हैं। हमारी कल्याणकारी सरकार है, वह एक वेलफेयर स्टेट है। इस वास्ते हमारा यह परम कर्तव्य है कि जो पिछड़े हुये लोग हैं और जो हमारी सहायता के पात्र हैं उनकी हम सहायता करें। हमारी सहायता के जो पात्र हैं वे छोटे छोटे काश्तकार हैं और हमारा यह फर्ज है कि जितनी हम उनकी सहायता कर सकते हैं, हम करें। उनकी सहायता करने के

[श्री सिंहासन सिंह]

लिये हम रास्ता अवश्य ढूंढ सकते हैं। आज कल हम देखते हैं कि इन्स्पेक्टरों की भरमार है। फिर देखो इन्स्पेक्टर ही इन्स्पेक्टर नजर आते हैं, कोई फूड इन्स्पेक्टर हैं तो कोई कोआपरेटिव इन्स्पेक्टर हैं और कोई एग्रीकल्चर इन्स्पेक्टर हैं। ऐसा मालूम होता है कि It has become a Government of Inspectors, by Inspectors, for Inspectors.

हमने एक कोआपरेटिव सोसाइटी का केस किया। केस दफा ४०६ के अन्तर्गत चलाया गया था। यह केस कोआपरेटिव सोसाइटी के सभापति पर, उसके सेक्रेटरी पर और इन्स्पेक्टर पर चलाया गया था और यह भ्रष्टाचार का केस था। जो सभापति था न वह पढ़ा हुआ था और न ही सेक्रेटरी कुछ पढ़ा हुआ था। वे लोग अपने नाम भी ठीक तरह से नहीं लिख सकते थे। इस केस में इन्स्पेक्टर व उपरोक्त व्यक्ति बैंक से ६,००० रुपए लाये और जब वह रुपया वितरण किया गया तो उसमें से कोई आठ नौ सौ रुपये गायब हो गये। जब यह केस अदालत में गया तो वहां पर सभापति और सेक्रेटरी को तो चार वर्ष की सजा हो गई और इन्स्पेक्टर साहब छूट गये। उनका कुछ भी नहीं हुआ। तो यह हालत हमारी कोआपरेटिव सोसाइटीज की हैं। सारा काम तो इन्स्पेक्टर करते हैं और बाद में कागजात दस्तखतों के लिये सेक्रेटरी और सभापति के पास चले जाते हैं क्यों कि वे कमेटी के मेम्बर होते हैं और कमेटी के मेम्बर होने के नाते जब वे दस्तखत कर देते हैं तो उनको जेल जाना पड़ता है। अब घंटी बज चुकी है....

सभापति महोदय : तीन दफा बजाई जा चुकी है।

श्री सिंहासन सिंह : मैं अभी खत्म किये देता हूं।

तो मुझे यह कहना है कि जो सुझाव इस कमेटी ने दिये हैं उन पर गवर्नमेंट को विचार करना चाहिये और शीघ्र किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिये।

जहां तक इस प्रस्ताव का सम्बन्ध है हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट इसे स्वीकार करेगी और इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में यह एटिचूड नहीं बरतेगी कि जो बात उनके अधिकारियों की तरफ से आये वह तो मान ली जाये और जो चीजें हमारी तरफ से पेश हों उनको अस्वीकार कर दिया जाये। अगर ऐसा हुआ तो हमारा यहां आना बेकार सा ही हो जाता है। इस वास्ते मेरी गवर्नमेंट से प्रार्थना है कि वह इस प्रस्ताव को मान ले और मानने के बाद सक्रिय रूप से इस पर विचार करे और बजट सेशन से पहले पहले इसको कार्यान्वित करे। मैं कहना चाहता हूं कि जिस काम को करने की किसी की इच्छा होती है वह अपने रास्ते में से जो अड़चनें आती हैं उनको दूर कर देता है और उसके लिये रास्ता साफ हो जाता है।

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि गवर्नमेंट इसे स्वीकार करेगी।

सभापति महोदय : सेठ अचल सिंह।

Shri Raghavaiah (Ongole): Mr. Chairman, you would look this side also.

Mr. Chairman: Is this the way to attract attention? If everybody adopts the name tactics, what will happen?

Shri Raghavaiah: You were not looking on this side.

सेठ अचल सिंह (जिला आगरा-पश्चिम): यह जो प्रस्ताव पेश किया गया है यह एक बहुत ही अहम प्रस्ताव है। इसका सम्बन्ध २५ करोड़ जनता से है। आपको मालूम ही है कि ७० परसेंट लोग खेती का काम करते हैं। जिस वक्त तक जमींदारी उन्मूलन कानून पास नहीं हुआ था और जमींदार लोग कायम थे उस वक्त तो जमींदारों से और बोहरों से किसानों को कर्जा मिल जाया करता था और काश्तकारों का काम चल जाया करता था। लेकिन जमींदारों के खत्म होने के बाद से उनके लिये रुपया लेने के साधन भी

खत्म हो गये हैं अब उनको रुपया देने वाला कोई नहीं है इस वास्ते कोई ऐसी व्यवस्था जरूर होनी चाहिये जिस के जरिए से कास्तकार कर्ज के रूप में रुपया ले सकें। अब उन लोगों को दो तीन रुपया प्रति सैंकड़ा ब्याज देने पर भी रुपया नहीं मिलता है। अभी हाल की बात है फसल के मौके पर आने ऐसा होगा कि गेहूं, चने, जौ, तिलहन इत्यादि के भाव गिर गये थे और काश्तकारों को मजबूरी के दर्जे उन्हीं भावों पर अपनी फसल को बेचना पड़ा क्योंकि जो उन्होंने कर्जा लिया हुआ था वह अदा करना था, और लगान (rent) अदा करना था और इसी तरह से उन पर दूसरे खर्चों का भार भी था। कोई सोसाइटी या इंस्टीट्यूशन के न होने के कारण उनको कहीं से एडवांस रुपया नहीं मिल सकता था और जो भाव बाजार में था उसी भाव पर उनको अपनी फसल बेचनी पड़ी। इसका नतीजा यह हुआ कि व्यापारी के हर माल में ड्योढ़े हो गये और कास्तकार को रुपये में दस आने मिले। इस वास्ते इस किस्म के बैंक का होना बहुत जरूरी है जो कि काश्तकारों को रुपया एडवांस कर सके। हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट की हमदर्दी काश्तकारों के साथ है और उसका यह विचार है कि काश्तकार और गवर्नमेंट के बीच कोई मिडलमैन न रहे, न जमींदार हों और न बोहरा हों। उसका सम्बन्ध सीधे काश्तकार के साथ हो। इसका नतीजा यह होगा कि काश्तकार को कहीं से कर्जा नहीं मिल सकेगा और गवर्नमेंट को ही उसके लिये कर्ज का इन्तजाम करना होगा।

इस वास्ते मेरे विचार में अगर इस किस्म के बैंक खुल जायें जो कि काश्तकारों को रुपया एडवांस कर सकें तो हमारे देश की हालत अच्छी हो सकती है। जो यह सुझाव इस प्रस्ताव में दिया गया है यह बहुत ही अच्छा सुझाव है।

अभी हाल ही में स्टेट बैंक कायम हुआ है और उसकी शाखाएं खोलने की बात भी चल रही है। लेकिन मेरे ख्याल में इस बैंक की उतनी शाखाएं नहीं खुल सकेंगी जितनी कि हम चाहते हैं खुलें। जो प्रस्ताव पेश किया गया है उसका मतलब यह है कि हर गांव में एक एक शाखा बैंक की होनी चाहिये जिससे कि काश्तकारों को रुपया मिल सके और उनका काम चल सके। इसलिये मैं समझता हूं कि जो प्रस्ताव पेश किया गया है यह बहुत ही जरूरी प्रस्ताव है और मैं आशा करता हूं कि गवर्नमेंट इसे स्वीकार कर के हमारी ८० प्रति शत जनता को राहत दिलाएगी और देश का फायदा करेगी।

Mr. Chairman: Pandit C. N. Malviya.

Shri Raghavaiah: You must divide the time with the Opposition also.

Mr. Chairman: I do not want to be dictated to in this manner.

Shri Raghavaiah: I am only making a suggestion.

Mr. Chairman: I know that the hon. Member has made the suggestion not once, but twice. I find that the hon. gentleman has just come in, whereas these gentlemen have been standing for four or five times.

Shri Raghavaiah: I stood more than four or five times.

Mr. Chairman: Then, I may not have seen him standing. But I have seen these gentlemen standing four or five times. It is unfortunate that I will not be able to give the hon. Member a chance to speak in connection with this resolution because the time is going to be up and I have yet to call the gentleman, who moved the resolution, at 3-50.

Shri Raghavaiah: I do not require more than five minutes.

Mr. Chairman: Now, I have called the other Member.

Pandit C. N. Malaviya (Raisen) *rose*.

Shri A. C. Guha: When is Government to reply?

Mr. Chairman: Government has already spoken.

The Minister of Agriculture (Dr. P. S. Deshmukh): I would like to supplement what has been said if you will give me ten minutes.

Mr. Chairman: If the hon. Minister had suggested it to me previously, I would have called upon him, but now so far as the Mover of the resolution is concerned, he must be enabled to give a reply, and I propose to call him at 3-50, because the time for the resolution will finish at 4-05.

Dr. P. S. Deshmukh: Then, two or three minutes will be enough.

Mr. Chairman: All right.

पंडित सी० एन० मालवीय: जो प्रस्ताव पेश किया गया है उसका मैं स्वागत करता हूं। जो रूरल क्रेडिट को सर्वे करने के लिये कमेटी मुकर्रर हुई थी उसकी रिपोर्ट सामने आ गई है। उस कमेटी ने गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा इंतजाम करने का सुझाव दिया है जिससे कि रूरल क्रेडिट का मसला हल हो जाये। इसलिये इस रेजोल्यूशन की स्पिरिट को गवर्नमेंट ने स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही साथ गवर्नमेंट ऐसे इंस्टीट्यूशन्स बनायेगी ही, जिनके द्वारा रूरल क्रेडिट का इन्तजाम हो, इसलिये इस रेजोल्यूशन को मंजूर कर लेने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि इसका सुझाव भी उन सुझावों से मिलता जुलता है। मैं इस हाउस का ज्यादा समय न लेता हुआ दो तीन सुझाव देना चाहता हूं। इस वक्त किसानों की अवस्था यह है कि---मैं खास तौर पर भोपाल की मिसाल देना चाहता हूं---मुझे भय है कि जिस रफ्तार से हम जा रहे हैं, उससे आगे चल कर हमें कई खतरात का सामना करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने १९५३-५४ में एपेक्स बैंक का बजट मन्जूर किया और अब जा कर पिछले मार्च में उसका कुछ रूप बना है। अभी तक उस की कोई कार्यवाही शुरू नहीं हुई है। इसी तरह से भोपाल में गवर्नमेंट ने "गो मोर फूड" और तकावी लोन के सिलसिले में कर्जे दिये थे। वे उस वक्त दिये गये थे, जब कि भाव काफी तेज थे। अब भाव गिर गये हैं। इस बात का ख्याल न रखते हुये गवर्नमेंट किसानों से एक बिजिनेस-मैन की मैन्टैलिटी से उन कर्जों को वसूल करने जा रही है। इस वजह से किसानों की हालत दुरुस्त नहीं हो पा रही है। मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट बिजिनेस मैन्टैलिटी से काम नहीं कर रही है और न ही करना चाहती है। अगर ऐसा होता तो "गो मोर फूड" के सिलसिले में कर्जे न दिये होते। ऐसी सूरत में मेरा सुझाव यह है कि अगर हम इस वक्त रूरल क्रेडिट को जारी करके किसानों की हालत को दुरुस्त रखना चाहते हैं, तो सब से पहले हमें गवर्नमेंट के सब लोन्ज को, सब टैक्निकल डिफिकल्टीज को अलग हटा कर एकजाई कर देना चाहिये और उनकी इन्स्टालमेंट्स को इतना रखना चाहिए कि किसान लैंड रैवेन्यू के साथ साथ उनको आसानी से अदा कर सकें।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भोपाल में आपने छः लाख रुपया दिया। परसों उसके बारे में इस हाउस में सवाल आया था। आप यह नहीं बता सके कि उन्होंने कितना गल्ला खरीदा है। यह आपकी इन-एफिशिएन्सी है कि आप ठीक तरीके से रिकार्डज नहीं रख पाते। भोपाल में सात रुपये मन तक गल्ला बिका है और अब पन्द्रह रुपये हो गया है। किसानों को कोई फायदा नहीं हुआ है। ट्रैक्टाइजेशन और दूसरे चार्जेज जो आप वसूल कर रहे हैं, तकावी वसूल करने के सिलसिले में किसानों के ऊपर जो ज्यादती हो रही है, जिस तरह से उनके माल दौलत को नीलाम किया जा रहा है, उससे एक तरफ तो उनकी कमर टूट रही है और दूसरी तरफ आईन्दा खेती करने में उनको फिर मुश्किल पड़ेगी। गवर्नमेंट की निगाह में तो वे नादिहन्दा हो गये हैं और उसकी तरफ से उनको कोई लोन नहीं मिलने वाला है। इसके अलावा कोई लोन का साधन उनके पास है नहीं। भोपाल में को-आपरेटिव की तारीख लिक्विडेशन की तारीख रही है और वह अभी तक मजबूत बुनियादों के ऊपर कायम नहीं हो पाई है। प्राईवेट लोन का स्ट्रक्चर तो खत्म हो गया है और इस तरह से भोपाल का किसान इस वक्त बिल्कुल अनाथ की तरह है। वह कहीं से लोन का इन्तजाम नहीं कर सकता है। मैं समझता हूं कि भारत के दूसरे प्रदेशों में भी यही हालत होगी। हमारे यहां जो क्रेडिट सिस्टम है, उसमें प्राइवेट सोर्सेज ज्यादा हैं। इस प्रस्ताव को पास कर के गवर्नमेंट को

इन प्राईवेट एजेंसीज को हारनेस करना चाहिये, जो आज भी लोन देती हैं, ताकि उनको कोआपरेटिव्ज में ला कर उस रुपये को इस्तेमाल किया जा सके। इस वक्त तो उन्होंने बहुत नामुनासिब तरीके अख्तियार किये हुये हैं। वे दस बारह परसेंट से ज्यादा सूद नहीं ले सकते, लेकिन वे उस रकम पर सूद दर सूद के हिसाब से अस्टाम्प लिखवा लेते हैं। अदालतों में उनकी जीत होती ही है और वे डिग्री ले कर कुर्की करवा लेते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आज चारों तरफ से किसानों का शोषण हो रहा है। फिर गवर्नमेंट के लोन्ज भी इतनी तरह के हो गये हैं—उनसे उनकी मदद तो जरूर हुई है—कि उनको बड़ी मुश्किल पेश आती है और वे बोझ से दबे जा रहे हैं। मेरा सुझाव है कि उन सब कर्जों को एकजाई कर दीजिये और उनकी इन्स्टालमेंट्स इतनी आसान कर दीजिये कि उनको आसानी से अदा किया जा सके। फिर उनका एक ही वक्त होना चाहिये। आज कल हालत यह है कि एक नोटिस आज मिलता है, कल दूसरा मिलता है और फिर तीसरा मिलता है।

आखिर में मैं फिर कहना चाहता हूं कि भोपाल में जो एपेक्स बैंक खोला गया है, मेहरबानी कर के जल्दी से उसकी कार्यवाही शुरू कीजिये। उस का काम वहां ही रुका हुआ है। मेरा ख्याल है कि दूसरी रियासतों में भी यही अवस्था होगी।

इन बातों की तरफ आपका ध्यान दिलाते हुए मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

Dr. P. S. Deshmukh: The only points which I want to place before the House are with respect to the action which Government propose to take at a very early date, and as a result of which, I am sure, at least my hon. friend Shri Sinhasan Singh would be amply pleased, and there would be no need for him to support the resolution that has been moved.

The resolution is certainly a desirable one from certain points of view, and in any case I welcome it because it has given hon. Members of this House an opportunity to relate the condition of agriculture, agriculturists and agricultural credit in the country. But it is somewhat out of date because of the report of the Rural Credit Survey Enquiry Committee and its recommendations. I am glad they were read out to the House extensively by my hon. friend Shri Sinhasan Singh. I may roundly say that most of these recommendations, if not all, have been fully accepted by Government; and Government are at the present time engaged in giving effect to them as speedily as possible.

I shall relate briefly what are the particular decisions which the Government of India are going to give effect to. The Reserve Bank Act has been amended already in order to enable medium—and long-term loans being provided to State apex institutions, and an annual target of Rs. 150 crores by 1960-61 is aimed at. This will be partly from the Reserve Bank and partly from other sources. Secondly, a high level Board for the National Co-operative Development and Warehousing will be set up shortly with the hon. Minister of Food and Agriculture as its Chairman. This board will have representatives of the various departments and agencies concerned with the development of co-operation. A draft legislation for the setting up of this board and its auxiliaries, namely the All-India Ware housing Corporation and the State Warehousing Companies will be brought before Parliament, not in the near future or in the next session but during this current session. In the meanwhile, all the preliminary arrangements for the setting up of the corporation and the companies are being made.

Possible sites for these warehouses, without which my hon. friends' suggestion of having grain banks will not be possible, are being selected; designs for such warehouses are being finalised; lists of commodities to be stocked are being made; standard specifications etc. for the qualities of various commodities are under consideration; and the terms and conditions of warehousing and other details

[Dr. P. S. Deshmukh]

are being prepared in order to ensure proper planning and execution.

Next, a separate co-operation division has been organised in my Ministry in charge of a Joint Secretary, which has been done for the first time, in order to supervise all these activities and give early effect to the recommendations of the Rural Credit Survey Committee's Report. All these steps have also been taken into consideration by a Conference of Ministers of Co-operation who had assembled in Delhi in April last and a pattern of the development of co-operation in the field of credit, marketing, warehousing etc. has been laid down, which is being followed in the formulation of the second five year plans of the State Governments. Schemes formulated by the State Governments on the above basis are being received and would be discussed by the Ministry of Food and Agriculture and finalised for the Second Five Year Plan. Many of the reports of the States have already arrived, some are about to come, and all these recommendations would be put in their proper perspective and placed in the second five year plans, both of the Centre and of the States. Training has also not been neglected, and training of co-operative personnel is also being simultaneously taken care of with the co-operation of the Reserve Bank. A special committee has been appointed for this purpose and there will be one training centre for the superior staff, which is already running in Poona; three schools for the medium cadre staff will also be established, one in Poona, another in Madras and the third in Pusa, in Bihar. Two other centres on a regional basis are also being planned and places will be selected. This training will commence about the month of October 1955. Eight centres for training block level co-operative officers are also being organised. I have heard many complaints about the way in which co-operation has worked in the States. I am fully conscious of some of the defects pointed out; yet I feel that that is the only way we can succeed. It would be rather belated to have some other agency in the place of co-operatives to advance these credits and look to various other things which are, in fact, integrated with co-operation, for instance, warehousing or co-operative marketing. If it is to be marketing at profit to the growers and at less cost to the consumer, co-operative marketing is the only way. So I do not think it is possible to do without co-operatives, and in spite of the fact that some defects have been pointed out, which may be true and correct, all our energies will have to be diverted to correcting them rather than to go in for substitution of the co-operative method by some other method.

In view of what I have stated, I think the Resolution becomes somewhat out of date, because we have decided this as a result of a report which finds favour with almost every Member of this House. Since the Government have taken steps in a particular direction, it would not be possible for us to have now some other method of distribution of credit like a corporation which has been suggested by my friend. I hope with this explanation he will see his way to withdraw the Resolution and not press it because more than what was intended by him would probably be accomplished within a short time.

Shri Heda (Nizamabad): The hon. Minister has not touched upon the defects in the present arrangements under the Community Projects scheme.

Dr. P. S. Deshmukh: In the Community Project areas, we are trying to spread co-operatives as fast as possible. My friend, Shri Das, is correct in saying that our ideal has not been achieved, and the targets have not been accomplished. But we will try to remove those defects and we want to encourage and utilise these agencies, as a matter of fact, for development of co-operative societies.

Shri S. N. Das (Darbhanga Central): I am very grateful to all the Members who have supported wholeheartedly the Resoultion moved by me.

Shri A. C. Guha: And not to the Government?

Shri S. N. Das: I am also grateful to the hon. Minister—both the Ministers—for their assurance that they are going to implement almost all the important recommendations made in the Report of the Committee of Direction appointed by the Reserve Bank of India. At the same time, I would like to draw the attention of the Government to the fact that although the importance and urgency of this problem has been realised by the Government, so far no practical steps have been taken, for the last seven years since India became independent. As my hon. friend, Shri B. K. Das has said, the Committee of Direction in its report stated that the whole co-operative movement in the country has failed, although it has said that in order to solve the problem of rural credit in the whole country, this co-operative movement will have to be rehabilitated. Even then, what does experience show? In spite of the efforts made so far, this movement has not succeeded and it has also been clearly stated in the Report that in spite of all the efforts, this movement was not able to contribute more than 3 per cent. of the total requirements of agricultural finance throughout the country. Therefore, I am a bit afraid that in spite of the assurances given, this problem, which is an appalling problem, a very vast problem, will not be solved to the satisfaction of the agriculturists who form a very large proportion of the Indian population.

Even the provisions of the Reserve Bank of India (Amendment) Bill and the State Bank of India Bill which this House passed recently, if implemented completely, will not even touch the fringe of the problem of this agricultural finance. I know that the Reserve Bank of India has two departments, the Rural Credit department and the Banking Development department. For the last seven years in this House and elsewhere, the importance of making sufficient and adequate provision for agricultural credit has been emphasised times without number, but we are told every time that that an inquiry or survey is being carried on and when the report will be available, Government will come forward with all their programme for agricultural finance. It is a matter of satisfaction that the Government have taken very little time to come to certain decisions, but even then I say....

Shri A. C. Guha: Very quick decisions.

Shri S. N. Das: .... that the problem is a vast one. It requires a very wide organisation at the all-India level to solve this problem. So far we have depended upon State Governments for the fulfilment of this programme, but as is clear from the reports of State Governments, in spite of all their efforts they have not been able to rehabilitate the co-operative movement in their respective areas. It shows that the Central Government, in co-operation with the Reserve Bank of India and the State Governments, should come forward with another statutory measure to establish a central agricultural—not only agricultural but also development—finance corporation, which will do all that is necessary—financial, organisational trading facilities and other things that are required—for the successful implementation of the agrcultural programmes in the country.

4 P.M.

My hon. friend, Shri A. C. Guha, has said that it is not feasible to have an apex without a base. I would say the present democratic government in this country and elsewhere is an apex without a base. In our Constitution, we have stated—Mahatma Gandhi had also stated—that in India to make democracy successful, we have to build seven lakh village republics, in seven lakhs villages throughout the whole country. But so far we do not see any appreciable progress made in this direction, even if *panchayats* have

[Shri S. N. Das]

been established in various parts of the country, they are not working satisfactorily because the officers of the Government, the police especially, do not co-operate. They do not desire that these *panchayats* should be given ample power. They think that the successful functioning of *panchayats* will interfere with their work. That is the lot of the *panchayats*. In India as we have made a strong government here at the Centre without the *panchayats* on which we have to rely, it is necessary, as circumstances show and as the report of the Committee of Direction shows, that special efforts should be made by the Government, with the co-operation of the Reserve Bank and other banks, particularly to provide ample and adequate agricultural and rural credit in the country. There is a small department of agricultural credit in the Reserve Bank of India. The Reserve Bank of India is a national organisation and it is saddled with very large responsibilities, especially the finance and commercial side of it. Although it is good that after so many speeches and emphasis laid in this House there was some amendment made in the Reserve Bank of India Act, which led to some provision being made for the accommodation to be given to State co-operative banks, we have seen so many times in various reports that even that little amount that was provided by the Reserve Bank of India could not reach the small cultivator. The State co-operative banks took the money and important States like Bombay and Madras and to some extent, U.P., took a very major part of that amount, and even there, I am informed, the agriculturists who live in remote villages have not been able to take advantage of the money that was provided by the Reserve Bank of India. For this great task of having basic institutions throughout the country, net work of co-operative banks and co-operative societies at various levels, it is all the more necessary that a central organisation like Agricultural Finance Corporation be established though our hon. friend Dr. Deshmukh said it is quite out of date. Even during the period of 50 years when we were under British rule, committees and commissions had been appointed and every committee and every commission emphasised that this was a great task to which the attention of the Government should be drawn. But in spite of that no specific action was taken by the Government. During the last seven years this problem has been mostly neglected. The most important question has been given the least attention by the Government and that is a matter for regret, but it is better to be late then never. The Government, I think, is paying the requisite attention that is necessary for the solution of this great task and I would request our friend Dr. Deshmukh to reconsider this as it is not out of date, because for a great task it is all the more necessary.....

Dr. P. S. Deshmukh: Not for all time, but only for the time being.

Shri S. N. Das: If there is a corporation at the Centre and if it has branches in the States, I think the co-operative movement will be co-ordinated with the working of the corporation, and the corporation will take the responsibility for everything that is necessary for the development not only of agricultural credit but also of all sorts of development, *e.g.* warehousing, storing and marketing. All these functions should be given to the corporation by the Reserve Bank of India which is now saddled with all these responsibilities. Instead of saddling the Reserve Bank with all these responsibilities, a separate organisation should be set up....

Dr. P. S. Deshmukh: They will be given to the Board and the Board will be constituted by an Act.

Shri S. N. Das: It is all the more necessary that we should have a separate organisation for this instead of having only a separate department in the Reserve Bank of India.

Shri A. C. Guha: There will be a separate organisation and it will have

its branches throughout the country. There will be also State corporations.

Mr. Chairman: I think the hon. Member would have been right if he brought up this question at the time when the State Bank Bill was discussed and said that there should be a separate department for this rural finance corporation. That was the proper time. Now he wants two things to be established, the State Corporation as well as the State Bank.

Shri S. N. Das: I have been trying to bring forward this resolution for so many years and it got the luck of ballot only this year. Now that my time is nearly over, I would like the Government to do all that is possible to implement the recommendations of the Committee of Direction and the assurances given and decisions taken to set up several important organisations. I would also like to withdraw my resolution, but I will say again that any failure on the part of the Government, as has been the case during the last five or seven years, will lead to very great resentment throughout the 70 per cent. of the population that depend upon agriculture—not only resentment but the whole scheme of the Government will fail if the agriculturists are not helped in time by the Government.

With this remark, I think that the two Ministries concerned would do all that is possible to implement the recommendations of this Committee and also other things that are not included in this report.

Mr. Chairman: I want to know whether Shri N. B. Chowdhury wishes that I should put his amendment to the vote of the House.

Shri N. B. Chowdhury (Ghatal): I beg leave to withdraw it.

Mr. Chairman: The hon. Member has seen that the Mover of the Resolution wants to withdraw, but under the rules I am bound to put the amendments to the vote of the House if they are pressed. Has the hon. Member leave of the House to withdraw his amendment?

The amendment was, by leave, withdrawn.

Shri B. K. Das: I also would like to withdraw my amendment.

The amendment was, by leave, withdrawn.

Shri Bogwat: I may also be allowed to withdraw my amendment.

The amendment was, by leave, withdrawn.

Shri Sinhasan Singh: Since the Mover is going to withdraw his Resolution, I would like to withdraw my amendment.

The amendment was, by leave, withdrawn.

Shri S. N. Das: I beg leave to withdraw my Resolution.

The amendment was, by leave, withdrawn.

RESOLUTION *RE.* APPOINTMENT OF A PAY COMMISSION

Shri D. C. Sharma (Hoshiarpur): I beg to move:

> "This House is of opinion that a Pay Commission should be appointed to go into the question of the pay structure of the country so that the disparity between the highest salary and the lowest salary is reduced to the minimum."

When I proposed this Resolution—and I had also the luck of the ballot,—I had not thought that it would create such a wide and deep interest all over the country. With a due sense of humility and modesty I must say that I have been receiving sheaves of letters from all the States of India. I have been receiving telephonic messages and the sources of communication were sometimes announced and sometimes kept a secret. Here is a letter which I have received from a gentleman. I do not know him but he calls himself a veteran Congressman. It is a very angry letter and a very bitter letter. I do not propose to read out that letter. But I must say that I should give at least one sentence from this letter: